दृष्टि *The Vision*

सामान्य अध्ययन (टेस्ट - II)

GENERAL STUDIES (Test - II)

मॉड्यूल - II / Module - II

DTVF/17–M–**GS2**

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

नाम (Name): Anil

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? | हाँ | | नहीं | |

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date): 9 | 30 July.

रोल न. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2017] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2017]:

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): Hindi

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature): Anil

नोट: प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।

Evaluation Analysis

Criterion	Grade
Introduction	B
Context	C
Language	C
Content	C
Conclusion	B
Structure	C
Current Link / Examples	B

MARKS: 58 /250

Copyright – Drishti The Vision Foundation

व्यापक विश्लेषण / Macro Analysis

- टू द प्वाइंट उत्तर लिखिए
- परीक्षा विषयवस्तु का मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों संदर्भों में उल्लेख कीजिए।
- गलत सूचना का उल्लेख न कीजिए।

Grade Card	
Grade 'A'	Very Good
Grade 'B'	Good
Grade 'C'	Satisfactory
Grade 'D'	Poor

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

1. "भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सत्य को खोजने की बजाय व्यावसायिक हितों से निर्देश प्राप्त कर रहा है।" उपर्युक्त कथन का 'पेड-न्यूज' की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये तथा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के संबंध में अपने सुझाव भी दीजिये। (250 शब्द) 12.5

"The fourth pillar of Indian democracy is now being guided by commercial considerations rather than pursuit of truth". Critically examine the above statement in the background of paid news and also add your suggestions in reference with the Representation of the People's Act, 1951. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अतिरिक्त चौथे स्तम्भ के रूप में 'मीडिया' को स्थापित किया जाता है। मीडिया को चौथा स्तंभ इसलिए ~~कहा~~ कहा जाता है कि निष्पक्ष रूप से जनता की आवाज को उठाकर इन तीनों स्तंभों को जनता से अवगत कराती है।

अभी हाल ही में 'मीडिया' पर पेड न्यूज जैसे आरोप लगाए गए। मीडिया चुनाव में किसी दल को जिताने के लिए उससे संबंधित सकारात्मक पक्षों को दिखाती है, जिससे कि जनता के बीच उस दल को लेकर एक सकारात्मक भाव बन सके। इसके बदले में उस मीडिया घराने को आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं।

मीडिया ~~की~~ के इस प्रकार के कृत्यों से लोकतांत्रिक निर्वाचन

पेड न्यूज को उचित परिभाषित करते हुए उल्लेख कीजिए

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

प्रणाली से निष्पक्ष रूप से नहीं चल पाती है।

भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जन 'प्रतिनिधित्व कानून 1951' बनाया गया है। यह कानून सभी दलों को एक समान स्तर प्रदान करता है। वस्तुतः जब कोई दल पेड-न्यूज का सहारा लेता है, तो इससे सभी दलों के चुनाव प्रणाली में एक समान स्तर प्राप्त नहीं हो पाता।

जन प्रतिनिधित्व कानून में वर्तमान पेड न्यूज संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए सुधार करने चाहिए जैसे- पेड न्यूज पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जानी चाहिए और इसके लिए न्यूज चैनल एवं राजनीतिक दल दोनों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए जो व्यक्ति ऐसे कृत्यों का दोषी पाया जाता है, उस पर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने पर प्रतिबंध होना चाहिए।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

इसको अपराध घोषित किया जाना है

अतः स्पष्ट है कि पेड न्यूज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए घातक और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन में कर इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

3

पेड - न्यूज़

आलोचनात्मक पक्ष के तहत सभी पक्षों पर पर्याप्त ध्यान दीजिए

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	C	B	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

2. यद्यपि भारत 'ब्राज़ील घोषणापत्र' का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है, फिर भी यहाँ सड़क दुर्घटनाओं को राष्ट्रीय संकट कहा जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Though India is a signatory to 'Brasilia Declaration', the road accidents can be termed as national crisis, illustrate. Examine the Motor Vehicle (Amendment) Bill, 2016. (250 words) 12.5

संक्षिप्त लेकिन उचित उल्लेख कीजिए

ब्राजील घोषणापत्र सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली ~~जन~~ ~~ब~~ हानि को रोकने से संबंधित है। भारत ब्राजील घोषणापत्र का हस्ताक्षरकर्ता देश है, फिर भी भारत में लगभग 5 लाख प्रतिवर्ष दुर्घटनाएं होती हैं, किंतु यह राष्ट्रीय संकट तब बन जाता है जब इन दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष 1.5 लाख मौतें होती हैं। जबकि विकसित देशों जैसे USA, चीन, रूस, ब्रिटेन, स्विटज़रलैंड इत्यादि में यह दर अत्यंत कम है।

वस्तुतः इसका दुर्घटना होने के ~~बाद~~ पश्चात समय पर चिकित्सा उपलब्ध न होना, लोगों द्वारा किसी पीड़ित मदद न

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

करना, सड़क सुरक्षा के लिए कोई विनियामक संस्था न होना इत्यादि।

इन्हीं सब समस्याओं के निराकरण के लिए भारत में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 लाया गया, जिससे सड़क दुर्घटना एवं उसके कारण होने वाली मौतों को रोका जा सके। इस विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान हैं।

→ इस विधेयक में एक 'एकीकृत वाहन रजिस्टर' का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी वाहन रजिस्टर होंगे।

→ ~~सभी~~ लाइसेंस प्राप्ति की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, जिससे योग्य एवं लोगों को ही लाइसेंस मिल सके एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे।

→ सड़क सुरक्षा, थर्ड पार्टी बीमा संबंधित प्रावधान भी इसमें जोड़े गए हैं।

→ सड़क खराब होने की स्थिति में 'कॉन्ट्रैक्टरों' की जिम्मेदारी तय

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

की गई है।

→ सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं।

निश्चित तौर पर यह विधेयक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएगा किंतु इसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे- शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, जुर्माने की राशि तय नहीं की गई है इत्यादि।

अतः स्पष्ट है कि विधेयक के क्रियान्वयन से भारत में दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों में कमी आएगी किंतु इसकी जो सीमाएं हैं, उनका भी समाधान आवश्यक है।

गलत सूचनाओं का प्रयोग न कीजिए

2

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	D	D	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

3. हाल ही में भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप के लिये चर्चा में रहा। क्या इस तरह की सेंसरशिप स्वामित्व (कॉपीराइट) और मौलिक अधिकारों का उल्लघन करती है? इसके विवादित पक्षों पर प्रकाश डालिये तथा भारतीय सिनेमा की समग्रता तथा भारत की विशिष्ट संस्कृति के संबंध में अपने सुझाव दीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recently censor board of India was in news for pre censorship of films. Is pre censorship violates copyrights and fundamental rights. Highlight the areas of controversy and put your suggestions for integrity of Indian cinema and ethnicity of Indian culture. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

हाल ही भारतीय सेंसर बोर्ड ने कुछ फिल्मों जैसे- उड़ता पंजाब, इंदु सरकार इत्यादि पर प्री- सेंसरशिप लगाई। वस्तुत: प्री- सेंसरशिप में बोर्ड फिल्म रिलीज होने के पहले ही उसके प्रसारण को रोक देता है।

प्री- सेंसरशिप को लेकर आलोचकों का मानना है कि यह स्वामित्व और व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है।

वस्तुत: बोर्ड का मानना है कि प्री- सेंसरशिप के कारण समाज में नैतिकता विद्यमान रहती है और किसी वर्ग की भावनाएं भी आहत होने से बचती हैं और उसका तर्क है कि व्यक्ति का

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

मौलिक अधिकार आत्यांतिक नहीं है।

भारत में यदि फिल्मों के प्रसारण को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। वस्तुतः स्वतंत्रता के कारण जहाँ रचनात्मकता में वृद्धि होती है, तो वहीं फिल्मों के माध्यम से सामाजिक स्थिति का भी पता चलता है।

किंतु भारत संस्कृति में जहाँ अनेकता में एकता, सर्व धर्म समभाव के सम्मान जैसे, सभी तत्व विद्यमान है, वहाँ पर किसी को भी निर्बाध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है।

अतः होना यह चाहिए कोई को प्रमाण पत्र देने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आवश्यक

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

हो तो ही किसी फिल्म के दृश्य के साथ काट - छांट करनी चाहिए। किंतु इससे फिल्म की आत्मा न मरे, इसका भी प्रयास करना चाहिए।

मद्रास उच्च न्यायालय के दिशा - निर्देश का आलोक राह के रूप में प्रयोग कीजिए

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	0.5	0.25	0.25	0.25	—
Grade	B	C	D	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

4. "संविधान संसद की शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है तथा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।" इस कथन को पृष्ठभूमि में रखते हुए क्या आप सोचते हैं कि संसद के कामकाज के नियंत्रण तथा इसे सुगम बनाने के लिये एक निगरानी आयोग की आवश्यकता समय की मांग है? (250 शब्द) 12.5

"The Constitution provides powers and immunities to the Parliament and the Parliament can amend the Constitution". In the background of above statement, do you think a monitoring commission is the need of the hour to control and facilitate the functioning of the Parliament? (250 words) 12.5

भारत में संविधान के द्वारा संसद को सर्वोच्च माना गया और संसद को कानून बनाने और संविधान संशोधन का अधिकार प्रदान किया गया है।

संसद की कार्यवाही से संबंधित उसे उन्मुक्तियां प्राप्त है और संसद के अंदर किए गए कोई भी कृत्य पर मुकदमा दायर नहीं कर सकता है।

इसी को लेकर यह मांग उठने लगी है कि संसद के कामकाज को नियंत्रित एवं सुगम बनाने के लिए निगरानी आयोग का गठन किया

2

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

जाना चाहिए।

वस्तुतः आयोग गठित हो जाने से संसद ऐसा कोई भी कानून या संविधान संशोधन नहीं कर पायेगी, जिससे जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या जो संविधान की भावना के प्रतिकूल हो, तो साथ ही संसद में होने वाले अमर्यादित कृत्यों को भी रोका जा सकता है।

किंतु वर्तमान में ऐसे निगरानी आयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि- एक तो संविधान के रक्षक के रूप में उच्चतम न्यायालय विद्यमान है, तो साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सदन के भीतर प्रत्येक सदस्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होनी ही चाहिए। और यदि कोई सरकार जन विरोधी

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कार्य करती है। उसे जनता निर्वाचन में उस दल को पराजित कर सकती है।

अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में निगरानी आयोग की आवश्यकता नहीं है किंतु फिर संसद सदस्यों को स्व नियंत्रण के माध्यम से आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए।

मौजूदा प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन कर उच्चतर नैतिक मानक निगरानी आयोग से बेहतर है।

2

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	A	A	C	B	B	

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

5. कुछ राज्यों और क्षेत्रों को प्राप्त विशेष दर्जा अधिक जनांदोलनों को भड़काने का काम करता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

The special status to some states and certain regions provoke more mass agitation. Critically examine. (250 words) 12.5

राज्यों एवं क्षेत्रों को विशेष दर्जा उनकी भौगोलिक परिस्थिति से देखते हुए प्राप्त है। जैसे- उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि विशेष राज्य का दर्जा इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि एक तो इनकी भौगोलिक स्थिति पहाड़ी है, तो साथ ही इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन से लगती है।

इसी प्रकार नागालैण्ड उनकी उत्तर पूर्वी राज्यों जनजाति क्षेत्रों को भी विशेष क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है।

किंतु अभी हाल ही में देखा गया कि विशेष दर्जे की मांग को लेकर आंदोलनों में बढ़ोत्तरी हुई है। जैसे अभी आंध्र

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

प्रदेश ने अपने लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, तो वहीं गोरखालैण्ड में अलग राज्य के गठन की मांग को जनांदोलन प्रारंभ हो गया है।

वस्तुत: राज्य विशेष दर्जा प्राप्त होने के कारण प्राप्त होने वाले लाभों जैसे- केंद्र से मिलने वाली अतिरिक्त सहायता, कर रियायत, विशेष सुविधाएँ को प्राप्त करना चाहते हैं।

इसीलिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग में वृद्धि हो रही है।

किंतु होना यह चाहिए कि विशेष राज्य एवं क्षेत्र का दर्जा विशेष कुछ परिस्थितियों के आधार

हालिया घटनाओं के आधार उदाहरण पर पत्र लिखा उल्लेख

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

पड़ मिलता है। अतः सभी राज्यों को सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करते हुए जनांदलोनों को खड़ा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

14 वें वित्त आयोग की सिफारिशें एवं नियामतों के निर्णय के मद्देनजर निष्कर्ष में आगे की राह (Way forward) का उल्लेख कीजिए।

4/3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	C	D	C	B	B-	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

6. (a) आम लोगों को त्वरित न्यायिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन समय की आवश्यकता है? 6

The creation of All India Judicial Services (AIJS) is the need of the hour for providing fast judicial services to the common people. 6

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

गठन से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लेख कीजिए

अभी हाल ही में भारत के विधि मंत्री ने भारत में सिविल सेवा के समान एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की बात कही।

वस्तुतः ~~अभी~~ वर्तमान में भारत में लगभग 3 करोड़ मामले लंबित हैं। इसका एक बड़ा कारण न्यायाधीशों की कमी है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठित होने से योग्य अभ्यर्थी सेवा की ओर आकर्षित होंगे और योग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संभव हो पाएगी जिससे एक तो न्यायाधीशों की कमी की समस्या का समाधान होगा तो वहीं यहीं न्यायाधीश अनुभव प्राप्त कर उच्च

गठन से जुड़ी आपत्तियों का भी उल्लेख कीजिए

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

एवं उच्चतम न्यायालय में भी नियुक्त होंगे जिससे उच्च न्यायपालिका को जजों की कमी की समस्या का समाधान होगा।

अतः हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा त्वरित न्यायिक सेवा प्रदान करने के आवश्यक है।

चुनौतियों और आगे की राह का भी उल्लेख कीजिए

(b) क्या आप सोचते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में अंधाधुंध बढ़ोत्तरी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही है? चर्चा करें। 6.5

Do you think mushrooming of administrative tribunals is creating a hurdle in judicial processes? Discuss. 6.5

भारत में अनुच्छेद 323A के अंतर्गत संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का गठन कर सकता है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने अनेक न्यायाधिकरण गठित किए।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

वस्तुतः प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में किसी विषय के विशेषज्ञ होते हैं, जो कि किसी क्षेत्र विशेष के मामले को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका समाधान करते हैं।

किंतु वर्तमान में देखा गया है कि ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध प्रत्येक उच्च न्यायालय में अपील करता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और विलंबित होती है।

फिर भी यह ट्रिब्यूनल के गठन से न्यायिक प्रक्रिया में तीव्रता भी आई है और लोगों को त्वरित न्याय प्राप्त हुआ है। अतः हम यह नहीं कह सकते कि सभी ट्रिब्यूनल के कारण न्यायिक प्रक्रिया विलंबित हुई है।

लाभ + चुनौतियों का प्रभावित उल्लेख।
अनधारणात्मक स्पष्टता/ दृष्टांत
संक्षिप्त
निष्कर्ष + आगे की राह
12

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	C	D	C	B	B	

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

7. चुनावों के वित्त पोषण से संबंधित पारदर्शिता में सुधार के संदर्भ में किये गए हालिया उपायों पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिये तथा राजनीतिक दलों की बेहतर जवाबदेही के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये? (250 शब्द) 12.5

Critically comment on the recent measures taken to improve transparency in electoral funding and what steps should be taken for better accountability of political parties. (250 words) 12.5

अभी हाल ही में चुनावों में वित्त पोषण से संबंधित पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार ने ₹2000 से अधिक ~~रुपए~~ चंदे की स्थिति में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को अनिवार्य किया है।

~~इसी~~ इससे राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में पारदर्शिता आएगी, क्योंकि अब यदि ₹2000 से ज्यादा का चंदा कोई व्यक्ति देता है, तो उसे ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी देनी होगी, इससे काले धन पर भी अंकुश लगेगा। क्योंकि अभी तक बड़ी मात्रा में काले धन का उपयोग चंदा के रूप में देकर उसको सफेद भी

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

किया जाता था।

किंतु ऐसा नहीं है कि इस सुधार में कोई कमी नहीं है। वस्तुतः अब यदि किसी व्यक्ति को ₹ 2000 से अधिक का चंदा देना है, और वह काला धन है, तो वह कई किस्तों में वह धन दे सकता है।

अतः राजनीतिक दलों की बेहतर जवाबदेही के लिए निम्न उपाय आवश्यक है -

- राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाया जाना चाहिए।
- राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले चंदे का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।
- राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकपाल का गठन किया जाना चाहिए।
- राजनीतिक दलों की वित्तीय

देवनागरी लिपि

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

अनियमितता की स्थिति में मान्यता रद्द करने संबंधी प्रावधान 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' में जोड़ना चाहिए।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सफल लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों में पारदर्शिता आवश्यक है।

निष्कर्ष + आगे की राह (Way forward)

3

लि. 20

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	0.5	.5	0.25	.5	✓
Grade	B	C	D		B	B	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

8. यह देखा गया है कि काला धन खपाने के लिये अचल संपत्ति मुख्य क्षेत्रों में से एक है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि कैसे हाल ही में लागू किये गए अचल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम (RERA) से भ्रष्टाचार को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा में मदद मिलेगी? (250 शब्द) 12.5

It is observed that real estate is one of the main domains of placing black money. Critically analyze that how recently adopted RERA (Real Estate Regulation and Development Act) will help in curbing corruption and protecting consumer rights. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारत में काला धन निवेश का एक बड़ा स्रोत अचल संपत्ति है। वस्तुतः रियल एस्टेट में व्यक्ति कि विक्रय कीमत दर्शाकर निवेश कर देता और आगे चलकर उसे अधिक दामों में बेच देता है। इससे एक तो जहाँ भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, तो वही रियल एस्टेट की कीमतों में वृद्धि होती है।

अभी हाल ही में सरकार ने रियल एस्टेट में भ्रष्टाचार रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 'अचल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम' पारित किया है, जिसमें निम्न प्रावधान है:-

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

- नियामक प्राधिकरण

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

- रियल एस्टेट विकास एजेंसी का गठन किया जाएगा, जो रियल एस्टेट कारोबार की निगरानी करेगा।
- किसी भी परियोजना में किसी व्यक्ति द्वारा दी गई रकम का 70% अलग से एक फण्ड में रखना होगा, जिससे उस राशि का उसी परियोजना में ही प्रयोग हो।
- किसी भी उपभोक्ता को प्रदान किए गए मकान की 5 साल की गारंटी देनी होगी। यदि इस अवधि के दौरान इसमें कोई कमी होती है, तो उसे निर्माता ही सुधारेगा।
- तय समय सीमा पर मकान उपलब्ध कराना होगा, ऐसा न होने की स्थिति में या तो राशि वापस करनी होगी या जब तक राशि वापस नहीं की जाती उस पर ब्याज देना होगा।

अच्छा प्रयास है

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

उपरोक्त प्रावधान निश्चित रूप से भ्रष्टाचार रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा में मदद देंगे। किंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे - इसमें शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान नहीं किया गया है, इससे छोटे निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि उन्हें 70% राशि अलग से रखनी होगी।

फिर भी यह अधिनियम रियल एस्टेट कारोबार को पारदर्शी एवं उपभोक्ता अनुकूल बनाने में सक्षम है।

गलत
सूचना
प्रस्तुत
कीजिए
यह प्रावधान किया गया है
आगे की राह से सम्बंधित निष्कर्ष लिखिए
3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	0.5	0.25	0.25	0.25	
Grade	B	C	D	C	CB	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

9. अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय के नाम पर किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रभावकारी अधिकार प्रदान करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Article 142 provides Supreme Court a virtual license to intervene in any matter in the name of complete justice. Critically analyze. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्णय, डिक्री जारी कर सकता है।

दरअसल अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने निर्णय को भी पूर्ण न्याय के आधार पर परिभाषित कर सकता है और आदेश या डिक्री जारी कर सकता है।

अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जाट आरक्षण मामले में कुछ युवाओं को जाट (OBC) का आरक्षण का लाभ देते हुए अनुच्छेद 142 के अंतर्गत

check it, देवनागरी लिपि सर्वोच्च न्यायालय

जाट और ... में शामिल किया जाए ...

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

आदेश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट के इसी अधिकार को लेकर कोर्ट की आलोचना की जा रही है कि इस प्रकार न्यायालय पूर्ण न्याय के आधार पर कोई भी निर्णय दे सकती है।

वस्तुतः संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को अधिकार इसलिए प्रदान किया, जिससे विरोधाभास की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे सके।

हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को यह संविधान द्वारा प्रदत्त है, अतः न्यायालय को भी इस अधिकार का प्रयोग करने में संयम बरतना चाहिए जिससे उस पर कोई आक्षेप न लगे और यदि

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

आवश्यक होने पर ही इस अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अनु. 142 और 50 के महत्व संतुलन बरकरार रखने का भी उल्लेख कीजिए

2

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	P	P	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

10. एक ऐसा देश जहाँ के अधिकांश नागरिक सरकार की नीतियों तथा सरकार के कामकाज को लेकर अनभिज्ञ हैं, वहीं विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर देना मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

A country in which most of its citizens are unaware of functioning of government and government policies; mandatory Aadhar card link to various services will create a trauma of confusion, analyze. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

74.04%

भारत की कुल आबादी की लगभग 65% जनसंख्या ही शिक्षित है। तो साथ ही शिक्षित जनसंख्या में से भी बड़ी संख्या मे लोग सरकारी नीतियों और सरकार के कामकाज से अनभिज्ञ है और सरकार ने विभिन्न सेवाओं को आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।

वस्तुत: अभी हाल ही में सरकार ने मिड-डे मील योजना के लिए भी आधार अनिवार्य कर दिया, तो साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के द्वारा प्राप्त होने वाली सब्सिडी के लिए आधार को अनिवार्य किया

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

गया है।

ऐसे में जहाँ एक वर्ग सरकार के इस कदम को उचित मान रहा है। उसका मानना है कि इससे सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की कमी आई है, तो वहीं एक ~~वर्ग~~ पात्र लाभार्थियों का चयन हो पा रहा है।

तो वहीं दूसरे वर्ग का मानना है कि भारत में लोगों में जागरूकता का अभाव है और सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर देने से वह सेवाओं से वंचित हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने भी सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य के स्थान पर वैच्छिक करने का निर्णय दिया है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आधार के आने से सरकारी योजनाओं

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

में लोकेप में कमी आई है, किंतु वर्तमान में ऐसी स्थिति विद्यमान नहीं है कि प्रत्येक सेवा के लिए इसे अनिवार्य किया जाए।

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	1.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	C	C	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

11. हाल ही में महिला श्रम बल भागीदारी को लेकर एनएसएस के आँकड़ों में प्रदर्शित किया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी स्थिर हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें गिरावट आ रही है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recent NSS data on women labour force participation has shown that women labour participation is stagnated in urban areas and sharply declining in the rural areas. Critically examine. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

NSS के आंकड़ो के अनुसार भारत में महिला श्रम बल नगरीय क्षेत्रों 24% और ग्रामीण क्षेत्रों में 29% पहुँच गया है। जो कि महिलाओं की श्रमबल में भागीदारी में गिरावट को प्रदर्शित करता है।

इस स्थिति के अनेक कारण जिम्मेदार हैं -

→ भारत पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ ~~प्रत्येक~~ महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सीमित है।

→ भारत में शहरी क्षेत्रों में कार्यालयों में महिलाओं के अनुकूल स्थिति नहीं है। जैसे- इन्हें यौन उत्पीड़न भेदभाव आदि का शिकार होना पड़ता है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

→ महिलाओं की सुरक्षा भी एक गंभीर प्रश्न है।
→ सार्वजनिक परिवहन महिलाओं के अनुकूल नहीं है।
→ महिलाओं को शिक्षा विशेषकर कौशल विकास संबंधी शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है।

महिलाओं की कार्यबल में वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए →
→ भारतीय समाज में विद्यमान पितृसत्तात्मकता को समाप्त किया जाना चाहिए।
→ महिलाओं को शिक्षा विशेषकर कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
→ महिलाओं के लिए अनुकूल कार्य दशाएँ होनी चाहिए। इस दृष्टि से भारत सरकार का मातृत्व सुरक्षा अधिनियम महत्वपूर्ण है।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की आधी आबादी को नजरअंदाज कर हम विकास नहीं कर सकते हैं। अतः यदि भारत को आर्थिक संवृद्धि प्राप्त करनी है, तो महिलाओं की कार्यबल में वृद्धि के लिए प्रयास करने चाहिए।

4

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	1.5	.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	C	C	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

12. प्राचीन काल में धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का महत्त्वपूर्ण विशेषता थी। हाल ही में धर्मनिरपेक्षता शब्द को समाचार माध्यमों में लगातार उछाला जाता रहा है। इस संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण कीजिये, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

From ancient times secularism was essential feature of Indian society. Recently the term secularism was flaunted continuously in media news. Analyze the current scenario in this regard; is secularism in India at risk? Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य होता है, कि सभी धर्मों का सम्मान और राज्य का भी कोई विशेष धर्म नहीं होगा बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा।

प्राचीन काल से ही भारत में धर्मनिरपेक्षता विद्यमान है। ~~प्राची~~ मौर्य काल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, तो साथ ही जैन एवं ~~हिन्दू~~ सनातन धर्म भी अपनी प्रगति करते रहे।

वर्तमान में अनेक समाचार पत्रों में

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान के मध्य की पृष्ठभूमि में धर्मनिरपेक्षता की विशेषता का संक्षिप्त ... उल्लेख कीजिए

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

देखने को मिलता है, जहाँ लिखा रहता है कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में है।

वस्तुतः भारत में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिनको लेकर यह कहा गया। जैसे - गौमांस को लेकर अल्पसंख्यकों पर हमला, दंगा की स्थिति तो साथ ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धार्मिक प्रतीकों के नाम पर दंगा हो गया।

लेकिन इस आधार पर यह कह देना कि भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, उचित नहीं है। भारत में धर्मनिरपेक्षता एक तो संविधान उल्लेखित है, तो वहीं उच्चतम न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढाँचा घोषित किया है। तो साथ ही भारतीय

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

संस्कृति अनेकता में एकता के सिद्धांत पर चलती है, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर कोई खतरा नहीं है और यह धर्मनिरपेक्षता भारत में विद्यमान रहेगी।

फिर भी विद्यमान चुनौतियों के मद्देनजर निष्कर्ष में आगे की राह (Way forward) के रूप में समाधान का उल्लेख कीजिए

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	4.5	0.25	0.25	0.25	
Grade	B	C	C	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

13. भारत सरकार अपने नागरिकों की खाद्य-सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित कर रही है लेकिन किसानों की सुरक्षा दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। खाद्य-सुरक्षा की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के उपाय भी सुझाइये। (250 शब्द) 12.5

Indian government is focusing on food security of its citizen but farmer's security deteriorating day by day. Critically examine challenges for food security and also mention suggestion for improvement of conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित कर ~~प्रत्येक~~ भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा के दायरे में ला दिया है। किंतु विडंबना यह है कि भारत में खाद्य आपूर्ति करने वाले किसानों की स्थिति दिन-प्रतिदिन निम्नतर होती ~~है~~ जा रही है।

खाद्य सुरक्षा की में निम्नलिखित चुनौतियां विद्यमान है-

→ भारत में प्रत्येक व्यक्ति प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा ~~है~~ है। भारत में दालों का उत्पादन कम है।

→ किसान किसानी छोड़कर किसी अन्य कार्य में संलग्न

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

खाद्य सुरक्षा एवं किसानों की स्थिति से जुड़ी जानकारी पर और अधिक ध्यान दीजिए

होना चाहिते हैं।

→ खाद्य उत्पादन के पश्चात उसका परिवहन एवं भंडारण बड़ी समस्या है।

→ खाद्य का समतामूलक वितरण भी चिंता का विषय है।

किसानों की स्थिति में सुधार के उपाय ⇒

→ किसानों को आधुनिक तकनीकी पर आधारित कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज रियायती दरों पर प्रदान किए जाने चाहिए

→ किसानों को सिंचाई सुविधा एवं विद्युत उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

→ किसानों को अपने फसल का उचित दाम मिले इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

इस दिशा में ई-नाम महत्वपूर्ण है।

→ ग्रामीण स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

→ परिवहन एवं भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

निष्कर्षतः हम कह सकते है कि यदि भारत को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करनी है, तो किसानों की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास करना आवश्यक है।

9

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

आपने अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास किया है

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	1.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	C	C	C	B	B	

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

14. भारत में एकल परिवार का प्रचलन संयुक्त परिवार से अधिक होता जा रहा है क्योंकि भारतीय समाज समूह की अपेक्षा व्यक्तिवाद की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Trends of nuclear family in India are more common than joint family as Indian society is heading towards more individualism than community. Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

वर्तमान में भारत में संयुक्त परिवार प्रथा की अपेक्षा, एकल परिवार की ओर अधिक आकर्षित है।

वस्तुतः औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के पश्चात भारत में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर रोजगार की तलाश में तीव्र गति से प्रवसन हुआ, जिससे शहरों में एकल परिवारों में वृद्धि हुई। वस्तुतः ग्रामीण जीवन में 'कृषि' का महत्वपूर्ण योगदान था और कृषि सामूहिकता पर बल देती है, क्योंकि कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

बल की ~~उपस्थिति~~ आवश्यकता होती है। अतः जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था टूटी, तो संयुक्त परिवार भी टूट गए।

पश्चिमी देशों के प्रभाव से भारत में व्यक्तिवादी अवधारणा में वृद्धि हुई। लोगों में अकेले रहने की चेष्टा बलवती हुई और संयुक्त परिवार का विघटन सामने आया।

भौतिकवादी संस्कृति ने भी भारत में संयुक्त परिवार के विघटन को बढ़ाया। क्योंकि लोगों का मानना था कि उन्हें जीवन अपनी मर्जी से जीना है और एकल परिवार ज्यादा लोकप्रिय हुए।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न कारणों के ने भारत में संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन हुआ और लोग एकल परिवार की ओर उन्मुख हुए।

3

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	C	D	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

15. हमारी शिक्षा प्रणाली बड़े राजनीतिक समुदाय के रूप में ग्रामीणों को एकीकृत करने में असफल रही है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Our education system has failed to integrate the rural into the larger political community. Comment. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

हमारी शिक्षा प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान, जाति प्रथा, सांप्रदायिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव इत्यादि को मिटाने में समर्थ नहीं रही। इसी का परिणाम है कि ग्रामीण बड़े राजनीतिक समुदाय के रूप में एकीकृत नहीं हो सके।

वस्तुतः आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति की पहचान, उसका सम्मान जाति के आधार पर होता है। वह संगठित भी जाति के नाम पर होता है। इससे ~~इसमें~~ वह बड़े राजनीतिक समुदाय के रूप में ग्रामीणों को एकीकृत नहीं कर पाई।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

इतना ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। इस कारण भी वे संगठित नहीं हो पाए।

सांप्रदायिकता ने भी उन्हें संगठित होने से रोका।

अतः स्पष्ट है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक समन्वय स्थापित करने में असफल रही। सहारनपुर में हुए दलित - सवर्ण संघर्ष के रूप में इसे देखा जा सकता है।

तुलनात्मक रूप में सकारात्मक पक्ष का भी उल्लेख कीजिए।

2

आगे की राह (Way forward)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	A	A	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

16. यह माना जाता है कि विमुद्रीकरण नकदी-विहीन समाज को प्रेरणा देकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की विफलताओं की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

It is believed that the demonetization will provide thrust to the welfare programmes by providing stimulus to cashless society. Discuss this statement in the backdrop of failures of various welfare programmes. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

विमुद्रीकरण के पश्चात भारत में ~~डिजि~~ ~~डिजि~~ कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कही गई।

वस्तुतः कैशलेस होने से जहाँ सरकार को कर चोरी को रोकना आसान होगा, जिससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक खर्च कर सकेगी।

तो वहीं नकदी-विहीन होने के कारण भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी, जिससे नीतियों का उचित प्रकार से क्रियान्वयन हो

(margin: विमुद्रीकरण को परिभाषित करते हुए इस प्रकार लिखिए)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

सकेगा। उदाहरण के लिए पी. ओ. एस. प्रणाली में बड़ी मात्रा में लीकेज एवं भ्रष्टाचार की समस्या देखने को मिलती थी, वह समस्या नकदी-विहीन की स्थिति में संभव नहीं होगी।

नकदी-विहीन समाज अर्थ के होने से काला धन पर भी अंकुश लगेगा और सरकार काले धन के स्रोतों को रोककर इस धन का उपयोग जन कल्याण के लिए कर सकती है। उदाहरण के लिए किसान कल्याण सेस एवं गरीब जन कल्याण योजना के माध्यम से सरकार किसानों एवं गरीबों के कल्याण का प्रयास कर रही है।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

मनरेगा जैसी स्कीम में होने वाले भ्रष्टाचार को भी नकदी विहीन समाज के माध्यम से रोका जा सकता है।

अतः हम कह सकते हैं कि नकदी विहीन समाज देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सफल रहेगी, ~~जिससे~~ और सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।

(चुनौतियों के मद्देनज़र आगे की राह (Way forward) के रूप में निष्कर्ष लिखिए)

2

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	D	D	C	B	B	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

17. हाल ही में टी. हक समिति ने नीति आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी, इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ बताइए तथा इसका कार्यान्वयन किस तरह से ग्रामीण कल्याण और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा? (250 शब्द) 12.5

Recently T. Haque committee submitted its report to NITI Ayog; point out salient features of its report and how its implementation will enhance the process of rural welfare and social justice. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

~~टीक~~ टी हक समिति

'भू - सुधार' से संबंधित समिति है। टी॰ हक ~~के~~ समिति ने अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी जिसकी निम्न विशेषताएँ हैं -

→ समिति ने ~~कि~~ सिफारिस की है कि राज्यों को पट्टेदार अधिनियम में संशोधन करना चाहिए, जिससे मालिक एवं पट्टेदार के बीच संघर्ष उत्पन्न न हो।

→ समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने की सिफारिश की।

→ समिति ने भूमि को वास्तविक मालिकों को हस्तांतरित करने के लिए सरकार का प्रयास

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

करने की सिफारिस की।

वस्तुतः यदि टी० एक समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन ग्रामीण कल्याण एवं सामाजिक न्याय स्थापित की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है।

वस्तुतः मालिक एवं पट्टेदार के बीच समन्वय स्थापित होने से भारत में भी बड़े-बड़े फार्मों के रूप में खेती है, जिससे छोटे जोत के आकार संबंधी समस्या का समाधान हो जाएगा।

समिति भूमि के वितरण को भी सुनिश्चित करने की बात की, जिससे सामाजिक न्याय में प्रगति होगी।

रक्षक क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

सहकारी कृषि को बढ़ावा देने से किसानों की आय में वृद्धि होगी।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि टी हक समिति की सिफारिशें ग्रामीण कल्याण और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती।

उपोत्तिमो? ... मैं नजर निष्कर्ष आगे की राह (Way forward) के रूप में प्रस्तुत कीजिए

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	C	C	C	B	B	

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

18. किसानों की कृषि ऋण माफी केवल अस्थायी राहत है। उक्त कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 12.5

Waiving off farm loans is only temporary relief to the farmers. Critically examine above statement and give your suggestions for improving conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

किसानों की कृषि ऋण माफी अस्थायी राहत है। वस्तुतः किसानों की ऋण माफी से उन्हें तात्कालिक राहत तो प्रदान की जा सकती है। किंतु यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है।

वस्तुतः ऋण माफी से किसानों को निम्न लाभ होते हैं:-

→ वह ऋण के चक्र से मुक्ति पाते हैं।
→ वह नवीन ऊर्जा से कृषि करने को अग्रसर होते हैं।
→ वह नवीन तकनीक को अपनाने को प्रोत्साहित होते हैं।
→ किसानों के आत्मिक मनोबल में वृद्धि होती है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

किंतु कृषि ऋण माफी दीर्घकालिक समाधान नहीं है। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए ⇒

→ किसानों को नवीन तकनीक पर आधारित कृषि के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

→ किसानों को उन्नत बीज रियायती दर पर उपलब्ध करना चाहिए।

→ किसानों विद्युत एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

→ किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी उपलब्ध होनी चाहिए और बिचौलियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।

→ ग्रामीण स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

प्रभावी रहा है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

→ चूंकि भारत में जोत का आकार छोटा है अतः आय के अन्य विकल्प जैसे डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन इत्यादि को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यदि किसानों की समृद्धि के उपरोक्त उपाय अपनाने चाहिए।

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	C	C	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

(कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

19. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा, इन दोनों की तुलना कीजिये तथा इनमें वैषम्यता दर्शाइये। (250 शब्द) 12.5

The Consumer Protection Bill, 2015 will replace the Consumer Protection Act, 1986, compare and contrast both. (250 words) 12.5

(कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

उपभोक्त संरक्षण विधेयक 2015; उपभोक्त संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित बिंदुओं पर असमानता देखी जा सकती है ⇒

→ 1986 के अधिनियम में किसी उत्पाद का प्रचार करने वाले व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, किंतु 2015 के अधिनियम में उत्पाद का प्रचार करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की गई है।

→ 1986 के अधिनियम में सख्त सजा का प्रावधान नहीं था जबकि 2015 में उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देते हुए, आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।

2

गलत सूचना के उल्लेख, ✓ कीजिए

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

→ 2015 के विधेयक में उपभोक्ता की परिभाषा व्यापक की गई है।

→ 2015 के विधेयक में उपभोक्ता के हितों के लिए मुआवजा का भी प्रावधान किया गया है।

→ 2015 के विधेयक में उपभोक्ता न्यायालय को अधिक अधिकार प्रदान किए हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं के संरक्षण में 1986 का अधिनियम अपर्याप्त था इसीलिए 2015 में नया विधेयक लाया गया जो कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के अनुकूल है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

आगे की राह (Way forward)
~~आवश्यक निष्कर्ष~~

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	A	A	C	B	B	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

20. (a) लिंग गणनापत्र (Gender Scorecard) क्या है? कैसे यह भारत की आधी आबादी के कल्याण हेतु एक लाभकारी उपकरण बन सकता है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये। 6

What is Gender Scorecard? How gender scorecard can become a beneficial tool for welfare of half population of India. Illustrate. 6

लिंग गणनापत्र ग्रामीण स्तर पर बालिका एवं बालक की जन्म दर को दर्शाता है।

इस लिंग गणनपत्र से ग्रामीण स्तर पर कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है।

लिंग गणनापत्र में अपनी स्थिति दर्शाने के लिए लोग बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित होंगे।

लिंग गणनापत्र के कारण लैंगिक भेदभाव में कमी आएगी। और महिलाओं को विकास के समान अवसर प्राप्त होंगे।

लिंग गणनापत्र के

संतुष्ट शब्द द्वारा तैयार किया गया है/ संक्षिप्त रूप में कर सकते उल्लेख कीजिए

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

कारण बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर कम होगी।

अतः हम कह सकते हैं कि लिंग गणनापत्रक महिलाओं के कल्याण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकता है।

निष्कर्ष + आगे की राह (Way forward)

1/2

(b) उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2015 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। 6.5

Critically examine the Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016. 6.5

उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यसभा में प्राइवेट बिल के रूप में उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2015 लाया गया। जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं –

(क) धारा 377 को समाप्त

परिभाषित करते हुए उल्लेख कीजिए

कैसा बिल है और प्रावधान सही हैं

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

किया जाए।

→ उभयलिंगी व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित की जाए।

→ यदि कोई उभयलिंगी व्यक्ति परिवार में रहना चाहता है, तो 18 वर्ष की आयु तक उसे परिवार के साथ निवास करने का अधिकार प्राप्त है।

→ उभयलिंगी व्यक्तियों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार तक पहुँच स्थापित की जाए।

अतः स्पष्ट है कि किसी भी समावेशी समाज के विकास के लिए सभी वर्गों का समावेशन आवश्यक है और इस दिशा में यह विधेयक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

check it

लाभों एवं चुनौतियों का स्पष्ट उल्लेख कीजिए

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	C	D	C	B	B	

Feedback

Questions ....

Model Answer & Answer Structure ....

Evaluation ....

Staff ....

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

रफ कार्य के लिये स्थान

(Space for Rough Work)

Copyright – Drishti The Vision Foundation